

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

इन्द्रावती खण्ड प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, पिन-492001

दूरभाष कार्यालय-(0771-4024235 फ़ैक्स-2442132) वेब साइट-www.siccg.gov.in ईमेल-sic.cg@nic.in

क्रमांक 2401 /स्था/छगरासूआ/17

रायपुर, दिनांक 05/12/2017

प्रति,

DEC 2017

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,

महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 हेतु जानकारी भेजने के संबंध में।

—00—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के प्रावधानों के तहत राज्य सूचना आयोग वर्ष के अंत में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित कर राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायेगा। अतएव गत वर्ष की भांति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग को दी जाने वाली वार्षिक जानकारी के लिए कुल 8 प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। वार्षिक जानकारी जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित की जावेगी।

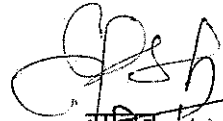
2. कृपया अवगत होना चाहेंगे कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत होने पर विधानसभा द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है। अतएव 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की चाही गई जानकारी संकलित कर दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

3. वार्षिक जानकारी विभागीय सचिवों के द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से एकत्रित कर एकजाई जानकारी आयोग को प्रस्तुत की जावेगी। जिन विभागों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त/संस्थाएँ/ट्रस्ट/अशासकीय संस्थाएँ आती हैं, उनके भी जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर विभागीय सचिव, विभागीय जानकारी के साथ भेजेगें। माननीय उच्च न्यायालय एवं एडवोकेट जनरल तथा विधिक सहायता प्रकोष्ठ कार्यालयों से संबंधित जानकारी विधि विभाग के द्वारा एकत्रित कर विभागीय जानकारी के साथ आयोग को भेजी जावेगी। इसी प्रकार विधानसभा कार्यालय की जानकारी संसदीय कार्य विभाग के द्वारा, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों (विधि विश्वविद्यालय सहित) की जानकारी सम्बंधित विभागों के द्वारा, एकत्रित कर विभागीय जानकारी के साथ आयोग को भेजी

जावेगी। महामहिम राज्यपाल कार्यालय/लोकायुक्त तथा अन्य अधीनस्थ विभागाध्यक्षों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विभागीय जानकारी के साथ आयोग को भेजी जावेगी। जिन विभागों के अंतर्गत मंडल, आयोग, निगम या अन्य संस्थाएँ हैं, उनके विभागीय सचिव उन आयोगों, मंडलों निगमों अथवा संस्थाओं से प्राप्त जानकारी विभागीय जानकारी के साथ सम्मिलित कर भेजेंगे। पंचायतों (ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायत/जिला पंचायतों) की जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संकलित की जावेगी। इसी प्रकार नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों एवं अन्य नगरीय संस्थाओं की जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा संकलित कर भेजी जावेगी। परिशिष्ट क. 4.8 में दी जाने वाली जानकारी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले की जानकारी उनसे संबंधित कालम में दी जानी है। गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी के आवेदकों की संख्या शहरी और ग्रामीण दोनों स्थिति में कालम 5 में प्रविष्टि करें तथा कालम 6 में अनुसूचित जाति के आवेदकों की संख्या, कालम 7 में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की संख्या, कालम 8 में पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की संख्या, कालम 9 में अन्य वर्ग के आवेदकों की संख्या अंकित करें।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के अंतर्गत सूचना आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विभागों का है। अतएव निर्देशानुसार अनुरोध है, कि अपने विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों से जानकारी परिशिष्ट 4.1 से 4.5 एवं परिशिष्ट 4.7, 4.8 और परिशिष्ट 4.9 संलग्न प्रपत्रों में एकत्रित एवं संकलित कर कृपया आयोग को दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक अनिवार्यतः भेजने का कष्ट करें।

संलग्न:-सहपत्र कुल 08 प्रपत्र


सचिव
छोगो राज्य सूचना आयोग
रायपुर

